नईदुनिया

आईपीओ में म्यूचुअल फंडों की रिकॉर्ड भागीदारी, छोटे शेयरों की ओर बढ़ा रुझान

नई दिल्ली

ईरान युद्ध के बाद से आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) में म्यूचुअल फंडों की भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। प्राइमडेटाबेस डाटा काम के आंकड़ों के अनुसार फरवरी के अंत में युद्ध शुरू होने के बाद से आए 13 आईपीओ में जुटाई गई कुल रकम का 32.3 फीसदी हिस्सा म्यूचुअल फंडों से आया है, जो पहले के 20 फीसदी के आंकड़े से कहीं अधिक है। यह बढ़ोतरी कई वर्षों के उच्च स्तर पर पहुंच गई है, जो छोटे बाजार पूंजीकरण वाली कंपनियों के प्रति परिसंपत्ति प्रबंधकों के बढ़ते रुझान को दर्शाती है। बढ़ती हिस्सेदारी का वार्षिक विश्लेषण: यह रुझान

परिसंपत्ति प्रबंधक अब 4,000 करोड़ रुपये से कम पूंजी वाली कंपनियों पर लगा रहे दांव

2023 से लगातार बढ़ता दिख रहा है। 2023 में आए आईपीओ से मिली कुल रकम का 17 फीसदी हिस्सा म्यूचुअल फंडों ने खरीदा था, जो 2024 में बढ़कर 20 फीसदी, 2025 में 22 फीसदी और जून 2026 तक 29 फीसदी तक पहुंच गया। हालांकि, ईरान युद्ध के बाद के 13 आईपीओ में यह आंकड़ा 32.3 फीसदी के साथ सबसे अधिक रहा, जो बाजार में म्यूचुअल फंडों के बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है। एक फाइनैंशियल सर्विसेज के अनुसार हाल के समय में बड़ी कंपनियों के मुकाबले छोटी कंपनियों के शेयरों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। यही वजह है कि परिसंपत्ति प्रबंधक अब उन कंपनियों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जिनका बाजार पूंजीकरण 4,000 करोड़ रुपये से कम है। आंकड़ों के मुताबिक, फरवरी के अंत से अब तक 4,000 करोड़ रुपये से कम बाजार मूल्यांकन वाली कंपनियों को लिस्टिंग वाले दिनों में औसतन 6.2 फीसदी का फायदा हुआ, जबकि इससे अधिक एमकैप वाली कंपनियों को औसतन 3.1 फीसदी का लाभ मिला। दिलचस्प बात यह है कि जहां बड़े आईपीओ में लगभग आधा हिस्सा म्यूचुअल फंडों ने खरीदा, वहीं 4,000 करोड़ रुपये से कम मूल्यांकन वाली कंपनियों के आईपीओ में उनकी हिस्सेदारी 10 फीसदी से कम रही। सिंह ने यह भी बताया कि भू-राजनीतिक तनाव और बाजार में आई गिरावट के कारण सेबी से मंजूरी प्राप्त कर चुकी कई बड़ी कंपनियों को अपने अपेक्षित मूल्यांकन पर फिर से विचार करना पड़ सकता है। यह देखना होगा कि कितनी कंपनियां कम मूल्यांकन पर सूचीबद्ध होने को तैयार होती हैं।

न्यूज ब्रीफ

बच्चों के शोषण पर मेटा की जवाबदेही तय, आईटी मंत्रालय ने भेजा समन

नई दिल्ली। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इंस्टाग्राम पर बाल यौन शोषण सामग्री (सीएसएएम) को बढ़ावा देने वाले विज्ञापनों के गंभीर आरोपों के मद्देनजर इंटरनेट कंपनी मेटा को तलब किया है। मंत्रालय ने कंपनी के एल्गोरिदम और ऐसे मामलों में उसकी जवाबदेही पर स्पष्टीकरण मांगा है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि राजस्व से जुड़े ऐसे मामलों में मेटा तीसरे पक्ष की सामग्री का हवाला देकर अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव के निर्देश पर मंत्रालय ने मेटा से स्पष्टीकरण तलब किया है। यह कार्रवाई बीबीसी की उस रिपोर्ट के बाद की गई है जिसमें दावा किया गया था कि मेटा के प्लेटफार्म पर बाल यौन शोषण सामग्री वाले वीडियो और विज्ञापन उसके एल्गोरिदम द्वारा बढ़ावा दिए जा रहे थे, भले ही कंपनी की नीतियां इसकी अनुमति नहीं देती हैं। मंत्रालय ने मेटा से ऐसे विज्ञापनों की स्वीकृति, सुधारात्मक उपायों और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए किए गए सुरक्षा उपायों पर विस्तृत जानकारी मांगी है। यह इस सप्ताह मेटा के खिलाफ दूसरी नियामक कार्रवाई है। इससे पहले सरकार ने व्हाट्सऐप के यूजरनेम फीचर को लेकर भी मेटा को नोटिस जारी कर उसे रोकने का निर्देश दिया था। आईटी अधिनियम की धारा 67बी के तहत बच्चों से संबंधित अश्लील सामग्री का प्रकाशन एक दंडनीय अपराध है। मेटा ने अपने बयान में कहा है कि उसकी बाल यौन शोषण सामग्री के प्रति शून्य-सहिष्णुता की नीति है और वह ऐसी सामग्री को हटाने के लिए उन्नत एआई का उपयोग करती है।

भारत-इजराइल द्विपक्षीय निवेश समझौता हुआ लागू, सीमा-पार निवेश को मिलेगा बढ़ावा

नई दिल्ली। भारत और इजराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता (बीआईए) शनिवार से प्रभावी हो गया है। भारत और इजराइल की सरकार ने 8 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में बीआईए पर हस्ताक्षर किए थे। वित्त मंत्रालय ने शनिवार को एक बयान में बताया कि भारत और इजराइल की सरकार के बीच 8 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में हस्ताक्षरित द्विपक्षीय निवेश समझौता 4 जुलाई से लागू हो गया है। बीआईए से सीमा पार निवेश में वृद्धि होने और भारत और इज़राइल के बीच आर्थिक साझेदारी के और गहरा होने की उम्मीद है। मंत्रालय ने कहा कि बीआईए द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और एक सुरक्षित और पूर्वानुमानित निवेश वातावरण को सुनिश्चित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। इस ऐतिहासिक समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच सुरक्षित निवेश का माहौल बनाना और सीमा-पार निवेश को बढ़ावा देना है, जिससे द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और गहरी होगी। वित्त मंत्रालय ने कहा कि बीआईए निवेश और निवेशकों के निवेशों की सुरक्षा में मजबूत है, साथ ही साथ वैध सार्वजनिक नीति के उद्देश्यों के अनुरूप संप्रभु नीतिगत स्थान बनाए रखने के लिए पर्याप्त लचीला भी है। यह अंतरराष्ट्रीय निवेश कानून के आधुनिक सिद्धांतों और विकसित होते न्यायशास्त्र को दर्शाता है।

आरबीआई ने बीओबी पर लगाया 63.6 लाख का जुर्माना

मुंबई । भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने नियामक मानकों के उल्लंघन के आरोप में बैंक आफ बड़ौदा (बीओबी) और जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक के निरीक्षण में इन वित्तीय संस्थाओं में कई कमियां उजागर हुईं। बैंक आफ बड़ौदा पर 63.6 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है, क्योंकि एक वैधानिक निरीक्षण में पाया गया कि बैंक ने कुछ ऋण खातों में निर्धारित दर से अधिक ब्याज वसूला। इसके अतिरिक्त, बैंक कुछ ग्राहकों के केवाईसी रिकार्ड को निर्धारित समयसीमा के भीतर सेंट्रल केवाईसी रिकार्ड्स रजिस्ट्री पर अपलोड करने में भी विफल रहा। इसी क्रम में जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड पर 3.1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। कंपनी केवाईसी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के साथ-साथ खातों के जोखिम वर्गीकरण की छह महीने में एक बार समीक्षा करने की प्रणाली लागू करने में नाकाम रही। आरबीआई ने स्पष्ट किया कि ये जुर्माने केवल नियामक अनुपालन में पाई गई कमियों के लिए हैं और इनका उद्देश्य किसी भी लेनदेन की वैधता पर टिप्पणी करना नहीं है।

केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने खिलौना उद्योग से निर्यात को 10 गुना बढ़ाने का किया आह्वान

नई दिल्ली

केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को भारतीय खिलौना निर्माताओं से अगले चार वर्षों में खिलौनों के निर्यात को 10 गुना बढ़ाने का लक्ष्य रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भारत-पेरू के बीच मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के लिए चल रही वार्ता के जल्द संपन्न होने की संभावना नहीं है। हालांकि, वाणिज्य मंत्री ने भारत-कनाडा एफटीए के संबंध में सकारात्मक संकेत दिए।

पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में आयोजित 17वें टाय बिज इंटरनेशनल बी2बी एक्सपो 2026 में खिलौना आयात करने वाले देश से निर्यातक बनने तक के भारत के सफर का ज़िक्र करते हुए कहा कि यह सेक्टर और भी तेजी से बढ़ने के लिए तैयार है क्योंकि हाल ही में संपन्न मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) से नए बाजार खुलेंगे। उन्होंने खिलौना उद्योग से कहा कि वे क्वालिटी, सुरक्षा और ग्लोबल इंटरनेशनल बी2बी एक्सपो को संबोधित करते हुए यह बात कही। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने भारतीय खिलौना उद्योग से अगले चार वर्षों में खिलौनों के निर्यात को 10 गुना बढ़ाने का लक्ष्य तय करने का आह्वान किया। उन्होंने अपने संबोधन में खिलौना उद्योग को आश्वासन दिया कि सरकार गुणवत्ता मानकों (क्यूसीओ) को वापस नहीं लेगी। पीयूष गोयल ने पूरे भारत में खिलौना निर्माण क्लस्टर्स के लिए आधुनिक टेस्टिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया है।

वाणिज्य मंत्री ने 17वें टाय बिज इंटरनेशनल बी2बी एक्सपो 2026 में खिलौना आयात करने वाले देश से निर्यातक बनने तक के भारत के सफर का ज़िक्र करते हुए कहा कि यह सेक्टर और भी तेजी से बढ़ने के लिए तैयार है क्योंकि हाल ही में संपन्न मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) से नए बाजार खुलेंगे। उन्होंने खिलौना उद्योग से कहा कि वे क्वालिटी, सुरक्षा और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को प्राथमिकता दें, ताकि वैश्विक खिलौना निर्माण और निर्यात हब के तौर पर भारत की स्थिति और मजबूत हो सके।

गोयल ने यहां आयोजित 17वें टाय बिज इंटरनेशनल बी2बी एक्सपो से इतर संवाददाताओं से कहा, कुछ चिंताएं हैं, कई ऐसे उत्पाद हैं, जहां हम उन्हें बाजार पहुंच की अनुमति नहीं दे सकते। मुझे नहीं लगता कि पेरू के साथ एफटीए बहुत जल्द होने जा रहा है। हालांकि, उन्होंने भारत-कनाडा एफटीए के संबंध में सकारात्मक संकेत दिए।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने कहा कि कुछ उत्पादों में बाजार पहुंच संबंधी चिंताओं के कारण भारत-पेरू मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के लिए चल रही बातचीत के जल्द संपन्न होने की संभावना नहीं है। दूसरी ओर भारत-कनाडा एफटीए के संबंध में मंत्री ने बताया कि भारतीय अधिकारियों का एक दल बातचीत के अगले दौर के लिए सोमवार को कनाडा जाएगा।

गोयल ने कहा, कनाडा के साथ एफटीए वार्ता अच्छी प्रगति पर है। हमारी टीम अगले दौर की बातचीत के लिए सोमवार को जा रही है। हमारी कोशिश है कि हम अगले छह महीनों में इसे अंतिम रूप दे दें।

केंद्रीय मंत्री ने यह बताया कि वह 13 जुलाई को विदेश मंत्री एस. जयशंकर और सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रानिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ ब्रसेल्स जाएंगे, जहां वे भारत-यूरोपीय संघ (ईयू) व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद (टीटीसी) की बैठक में हिस्सा लेंगे।

डुउल्लेखनीय है कि भारत और पेरू के बीच प्रस्तावित एफटीए के लिए बातचीत साल 2017 में शुरू हुई थी। वैश्विक खिलौना बाजार लगभग 120 अरब डालर का है लेकिन इसमें भारत की हिस्सेदारी अभी मात्र 0.2 से 0.3 फीसदी है। हालांकि, पिछले चार वर्षों में खिलौनों के निर्यात में मजबूत वृद्धि दर्ज की गई है।

ईपीएफओ पोर्टल का बड़ा अपग्रेड, यूएएन सेवाएं अब उमंग ऐप पर

नई दिल्ली

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपने यूनिफाइड मेंबर पोर्टल को नए इंटरफेस और बेहतर सुरक्षा सुविधाओं के साथ अपग्रेड किया है। एक सप्ताह के रखरखाव के बाद दोबारा शुरू हुए इस पोर्टल पर अब यूएएन एक्टिवेशन और नया यूएएन जनरेट करने जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं सीधे उपलब्ध नहीं होंगी। इन्हें सुरक्षा और विश्वसनीयता बढ़ाने के उद्देश्य से उमंग ऐप पर स्थानांतरित कर दिया गया है। इस बड़े बदलाव के बाद, अब ईपीएफओ सदस्य उमंग ऐप के माध्यम से ही अपने यूएएन को एक्टिवेट कर सकेंगे।

इसके लिए आधार-आधारित फेस आथेंटिकेशन का उपयोग किया जा सकेगा। इसी तरह नया यूएएन जनरेट करने या पहले से मौजूद पीएफ खाते से नए यूएएन को लिंक करने की प्रक्रिया भी अब केवल उमंग ऐप पर ही उपलब्ध होगी, जिसके लिए मोबाइल नंबर सत्यापन आवश्यक होगा।

हालांकि ईपीएफओ ने अपने यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पर यूएएन

सुरक्षा और विश्वसनीयता बढ़ी, पोर्टल पर यूएएन ढूंढना हुआ आसान

ढूंढना पहले से आसान बना दिया है। सदस्य अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज कर, पहचान प्रमाण अपलोड करने और ओटीपी सत्यापन के बाद अपना यूएएन दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सदस्य की मृत्यु के बाद नामिनी या लाभार्थी द्वारा किए जाने वाले डेथ क्लेम और पेंशन से जुड़े दावे पहले की तरह ईपीएफओ के यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पर ही उपलब्ध रहेंगे।

उमंग भारत सरकार का एक आधिकारिक ऐप है, जो ईपीएफओ सहित विभिन्न सरकारी सेवाओं को नागरिकों के लिए अधिक सुरक्षित, डिजिटल और उपयोगकर्ता-अनुकूल बनाता है। इस कदम का उद्देश्य सेवाओं को और अधिक सुलभ और सुरक्षित बनाना है।

भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 5.65 अरब डालर घटा

नई दिल्ली। देश के विदेशी मुद्रा भंडार में 26 जून को समाप्त सप्ताह में 5.65 अरब डालर की बड़ी गिरावट दर्ज की गई, जिससे यह 666.93 अरब डालर रह गया। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, यह गिरावट पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण रुपए पर बढ़ते दबाव और केंद्रीय बैंक के डालर बेचकर बाजार हस्तक्षेप के बाद आई है। फरवरी में 728.49 अरब डालर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद से विदेशी मुद्रा भंडार में कमी देखी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 11 मई से देशवासियों से विदेशी मुद्रा की बचत करने, विदेश यात्राएं कम करने और एक वर्ष तक सोने की खरीदारी से बचने की अपील की है। आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक, इस सप्ताह स्वर्ण भंडार का मूल्य सर्वाधिक 5.39 अरब डालर घटकर 102.54 अरब डालर रह गया। वहीं, विदेशी मुद्रा आस्तियां (एफसीए) 15 करोड़ डालर और विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) 8.9 करोड़ डालर कम हो गए। एक अन्य आर्थिक घटनाक्रम में, शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी दर्ज की गई और बाजार लगातार तीसरे दिन बढ़त के साथ बंद हुआ। आईटी शेयरों में शानदार खरीदारी और अनुकूल वैश्विक संकेतों से बाजार को मजबूती मिली।

सरकार ने प्याज की खरीद कीमत 13 फीसदी बढ़ाकर 2,125 रुपये प्रति क्विंटल किया

नई दिल्ली

सरकार ने प्याज की खरीद कीमत 13 फीसदी बढ़ाकर 2,125 रुपये प्रति क्विंटल कर दी है। इससे प्याज किसानों को बेहतर रिटर्न मिलेगा और बफर खरीद मजबूत होगी। नई दरें 4 जुलाई से प्रभावी हो गई है।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने शनिवार को जारी बयान में बताया कि केंद्र सरकार ने प्राइस स्टेबलाइजेशन बफर (कीमतों को स्थिर रखने के लिए बनाए गए स्टाक) के लिए प्याज की खरीद कीमत 13 फीसदी बढ़ा दी है, जो 1,875 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,125 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है। ये नई खरीद कीमत 4 जुलाई से प्रभावी हो गई है।

मंत्रालय ने कहा कि सरकार के प्राइस स्टेबलाइजेशन बफर के लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नाफेड) और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड (एनसीसीएफ) के जरिए प्याज की खरीद का काम चल रहा है। प्याज खरीद की ये नई कीमत प्याज किसानों को बेहतर आमदनी दिलाएगी और बफर स्टाक बनाने की कोशिशों में भी मदद करेगी।

वहीं, कृषि और किसान कल्याण विभाग के 2025-26 के दूसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार, प्याज का उत्पादन 307.37 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) रहने का अनुमान है, जो 2024-25 में हुए 307.67 एलएमटी के उत्पादन के लगभग बराबर है।

मंत्रालय ने कहा कि प्याज उत्पादन के इन अनुमानों को देखते हुए इस समय प्याज की कुल उपलब्धता चिंता का विषय नहीं है। हालांकि, कीमतों में सामान्य मौसमी उतार-चढ़ाव के कारण थोड़ी बढ़ोतरी की उम्मीद की जा सकती है। वहीं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में स्टाक का स्तर पर्याप्त है। फिलहाल, प्याज के भंडार में किसी भी तरह की कमी के कोई संकेत नहीं हैं।

आर्थिक आंकड़ों में बड़ा बदलाव, वास्तविक जीडीपी गणना में अब पीपीआई डिफ्लेटर

जून तिमाही से लागू होगी नई गणना प्रणाली; 31 अगस्त को जारी होंगे संशोधित अनुमान

नई दिल्ली

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) ने भारतीय आर्थिक आंकड़ों की गणना में एक महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की है। मंत्रालय अब जून तिमाही (वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही) से वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के आंकड़ों की गणना के लिए आउटपुट उत्पादक मूल्य सूचकांक (पीपीआई) को डिफ्लेटर के तौर पर इस्तेमाल करेगा। यह कदम देश के सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक संकेतक के आकलन के तरीके में एक

संरचनात्मक परिवर्तन लाएगा, जिसका उद्देश्य आर्थिक वास्तविकताओं को अधिक सटीक रूप से प्रतिबिंबित करना है। सरकारी अधिकारियों के अनुसार, सांख्यिकी मंत्रालय 31 अगस्त को पिछले वर्षों के लिए संशोधित वास्तविक जीडीपी अनुमान भी जारी करेगा, जिसमें डिफ्लेटर के तौर पर आउटपुट पीपीआई का इस्तेमाल किया जाएगा। इसी दिन वित्त वर्ष 2027 की अप्रैल-जून अवधि के लिए राष्ट्रीय लेखा के आंकड़े भी जारी किए जाएंगे। इस बदलाव का सीधा असर पिछले तीन वित्त वर्षों के आंकड़ों पर पड़ेगा। एक अधिकारी ने बताया, वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही का जीडीपी डेटा आउटपुट पीपीआई पर आधारित होगा। वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के लिए जारी अनुमान स्थिर कीमतों पर अनुमान से बदल जाएंगे क्योंकि अब इसमें पीपीआई को शामिल किया जाएगा। संशोधित श्रृंखला अगस्त में आएगी।यह महत्वपूर्ण निर्णय सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा 29 जून को जारी औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के आंकड़ों के बाद आया है, जिसमें थोक मूल्य सूचकांक की जगह आउटपुट-पीपीआई का इस्तेमाल डिफ्लेटर के तौर पर किया गया था। इस पृष्ठभूमि में, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने 15 जून को भारत का पहला उत्पादक मूल्य सूचकांक ढांचा जारी किया था, जिसमें आउटपुट पीपीआई, इनपुट पीपीआई और सेवा पीपीआई शामिल हैं।

सरकार गोल्ड मोनेटाईजेशन स्कीम 2.0 लान्च करने की तैयारी में

मुंबई। केंद्र सरकार एक बार फिर अपनी गोल्ड मोनेटाईजेशन स्कीम (जीएमएस) को नए सिरे से पेश करने की तैयारी में है। इसका मुख्य उद्देश्य घरों और लाकरों में पड़े अनुमानित 25,000 टन निष्क्रिय सोने को औपचारिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनाना है, जिससे देश का भारी सोने का आयात बिल कम हो सके और नकदी प्रवाह बढ़ सके। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस नई योजना में जौहरियों को भी कलेक्शन पार्टनर के रूप में शामिल किया जा सकता है, जिससे लोगों के लिए सोना जमा कराना आसान और भरोसेमंद बने। सरकार का लक्ष्य कुल 25,000 टन में से करीब 1,000 टन सोना बाजार में लाना है। यदि इसका सिर्फ 5 फीसदी हिस्सा भी सिस्टम में आता है, तो अर्थव्यवस्था में लगभग 8.5 लाख करोड़ रुपए की नकदी जुड़ सकती है और सोने का आयात बिल काफी कम हो सकता है। यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस अपील से भी जुड़ी है, जिसमें उन्होंने लोगों से एक साल तक सोना न खरीदने की सलाह दी थी। 2015 में शुरू हुई जीएमएस का प्रदर्शन कमजोर रहा, 10 सालों में सिर्फ 38 टन सोना जुटाया जा सका। इसकी मुख्य वजहें भावनात्मक लगाव, टैक्स का डर, और ब्याज दरों (2.25-2.5 फीसदी) तथा सोने की कीमतों पर अनिश्चितता थीं। नई योजना इन चुनौतियों को दूर करने का प्रयास करेगी।